अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वसुलभ स्वरूप की है। इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तथा केरल आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आती हैं।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों पर केन्द्रित करते हुए प्रवाही बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वर्गीय प्रो० लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की कार्य प्रणाली को अपनाकर योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर 10 कि० ग्रा० प्रति महीने की दर से खाद्यान्न जारी किए जाएंगे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों के आवंटन का हिसाब गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रख कर पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्न के औसत उठान के आधार पर किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उचित दर दुकानों के लिए निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करने तथा जिला कलेक्टर/जिला मैजिस्ट्रेट से लेकर आपूर्ति निरीक्षक के स्तर तक से उद्देश्य-पूर्ण परीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया है। उचित दर दुकान, तालुक जिला तथा राज्य स्तरों पर सर्तकता समितियां गठित की जानी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यपद्धति में अधिक पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है। इसका ब्यौरा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों में दिया गया है जिनको 24.2.97 को दोनों सदनों के पटलों पर रख दिया गया था। यह उम्मीद की जाती है कि इन उपायों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ज्यादा प्रभावी बनेगी।

Study on Vehicular Pollution in the Country

4484. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any study has been undertaken by Government directly or through some agency or study group, regarding the polluting effects of automobiles in Indian cities and towns and the extent of it in other countries; and

(b) the details of the data available regarding the above and the steps taken by Government or being considered by Government to check growth of pollution due to the non-implementation of pollution control measures or the lack of sufficient initiatives from Government?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) The Central Pollution Control Board have conducted major surveys to assess the vehicular pollution in 12 major matropolitan cities of the country. The surveys show that:

*Pollution load in Delhi almost equals the combined pollution load of Mumbai, Calcutta and Madras.

*Load due to emissions of carbon monoxide (64%) and hydrocarbons (22%) is the highest in all the cities. This is followed by oxides of nitrogen(12%). Emissions of sulphur dioxide are negligible.

*The major contributors to carbon monoxide and hydrocarbons are the two-wheelers and three wheelers which are mostly powered by the two-stroke engines.

The major contributors of oxide nitrogen are the diesel driven trucks and buses.

According to the Report of UNEP-WHO on "Global Pollution and Health", 1988, Delhi is the fourth most polluted city in terms of suspended particulate matter and 27th in terms of sulphur dioxide. 1st, 2nd and 3rd polluted city in the world are: Kuwait, Shenyang (China) and Xian (China). Whereas Mumbai and Calcutta are at 13th and 6th positions respectively in terms of suspended particulate matter.

A number of measures are being taken/proposed for controlling vehicular pollution in the country. These include the following:

(i) Gross emission standards for on-road vehicles and mass emission standards for all categories of new vehicles have been notified under the

Central Motor Vehicles Rules, 1989 and are being enforced by the Departments of Transport of the various States.

(ii) Stricter emission norms have been introduced with effect from 1.4.96 and stricter norms are to be introduced from 1.4.2000. The automobile manufacturers have to upgrade their technology to meet these emission norms.

(iii) Low-lead petrol (0.15 gramme per litre) has been introduced throughout the country from 1.1.1997.

(iv) A major programme for introduction of unleaded petrol and catalytic converter fitted vehicles is under implementation. The first phase covering the four metropolitan cities of Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai, came into effect on 1.4.95. In the next phase, effective from 1.1.99, catalytic converter fitted vehicles would be introduced in the Capitals of all States and UTs. Unleaded petrol is planned to be supplied throughout the contry from 1.4.2000.

(v) Diesel with a sulphur content of 0.5% has already been introduced in the four metropolitan cities of Delhi, Mumbai, Calcutta and Cehnnai, with effect from 1.4.95. Low sulphur diesel (0.25%) is planned to be supplied throughout the country from 1.4.1999.

(vi) Surveys have been conducted by the Central Pollution Control Board on the vehicular emissions in the major cities and towns in the country. The findings of the survey have been used for the preparation of measures for control as well as abatement of vehicular pollution in the major cities.

(vii) the ambient air quality of various cititcs and towns are being monitored through a network of 290 monitoring stations under the National Ambient Air Quality Monitoring Programme.

(viii) The Transport Department of the Government of NCT of Delhi, has launched an awareness campaign on vehicular pollution which includes health effects resulting from vehicular pollution, the maintenance measures for its control and the punitive action for violation of pollution control regulations. A Special Task Force, under the Chairmanship of Lt. Governor, Delhi, has been set up for control of vehicular pollution in Delhi.

मेघालय में वनों की अंधाधुंध कटाई

4485. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मेघालय में पिछले 10 वर्षों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई की गई है और वहां घने जंगलों का क्षेत्रफल कम हो गया है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे कौन से राज्य है जहां घने जंगल कम हुए हैं अथवा कम होते जाने की आशंका है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में घने जंगलों की अंधाधुंध कटाई पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार इस रोक के पक्ष में है?

पर्यावरण और वन मंत्री: (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।

बेतवा नदी की सफाई

4496. **श्री राघवजी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की बेतवा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है, यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये खर्च की जा चुकी है;

(ख) क्या यह सच है कि बेतवा के जल की शुद्धता में गत छह महीनों से कोई अंतर नहीं आया, अपितु जल अधिक अशुद्ध ही हुआ है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जल को शुद्ध करने के लिये निकट भविष्य में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या आगामी ग्रीष्म ऋतु में विदिशा